संकल्प पत्र से नगरीय निकायों का सुनियोजित व सर्वांगीण विकास होगा- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा घोषणा पत्र नहीं संकल्प पत्र जारी करती है, क्योंकि हम वादे पूरे करते हैं

जयपुर, 2 सितम्बर। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर प्रदेश के शहरों के सुनियोजित, आधुनिक एवं सर्वांगीण विकास के लिए 'नगरीय विकास संकल्प-पत्र 2026' जारी किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी, संगठन महामंत्री अजेय कुमार, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, संकल्प पत्र संयोजक व सांसद घनश्याम तिवाड़ी, सांसद मंजू शर्मा, संकल्प पत्र सह- संयोजक संतोष अहलावत, सौम्या गुर्जर ने संकल्प पत्र का विमोचन किया।

- "नगरीय विकास संकल्प पत्र-2026" का विमोचन करते हुए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी, संगठन महामंत्री अजेय कुमार, श्रवण बागड़ी, घनश्याम तिवाड़ी, मंजू शर्मा, संतोष अहलावत व सौम्या गुर्जर भी साथ थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को 'नगरीय विकास संकल्प-पत्र 2026' जारी किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी, संगठन महामंत्री अजेय कुमार, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, सांसद घनश्याम तिवाड़ी, सांसद मंजू शर्मा, संतोष अहलावत, सौम्या गुर्जर मौजूद थे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने संकल्प पत्र विमोचन के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र नगरीय क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित करेगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र नहीं, संकल्प पत्र जारी करती है। घोषणा पत्र सिर्फ घोषणाओं का होता है, जबकि संकल्प पत्र काम करने का संकल्प होता है। उन्होंने कहा, भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2023 में जारी किए संकल्प पत्र में से 78 फीसदी वादों को महज 32 माह में पूरा कर दिया। अब नगरीय निकायों का संकल्प पत्र जारी कर नगरीय निकायों का कायाकल्प करना होगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि संकल्प-पत्र में अगले पांच वर्षों में शहरों के अलग-अलग आय वर्गों के लिए एक लाख आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करने का संकल्प लिया गया है। वहीं 7 लाख से अधिक घरों में कनेक्शन, महिलाओं की सुविधा के लिए 2,000 पिंक टॉयलेट्स तथा नए एवं बाहरी आवासीय क्षेत्रों में 15 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगाने का लक्ष्य रखा गया है। डंपिंग साइट्स पर वर्षों से जमा पुराने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाएगा। घर-घर कचरा संग्रहण करने वाले वाहनों में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा।

नीट पीजी में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के समक्ष मेंशन करें। नीट पीजी 2026 की मुख्य परीक्षा 30 अगस्त 2026 को देशभर में आयोजित की गई थी। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (एनबीईएमएस) ने तकनीकी गड़बड़ी से प्रभावित 2,445 अभ्यर्थियों के लिए नीट पीजी 2026 की परीक्षा दोबारा कराने का फैसला किया है। इस परीक्षा में 2,65,980 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इनमें से 2,63,535 अभ्यर्थियों की परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी हो गई थी। तकनीकी गड़बड़ी से प्रभावित 2,445 अभ्यर्थियों की परीक्षा सामान्य तरीके से पूरी नहीं हो सकी। इन्हीं अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया गया है।

आरक्षण में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कैंसर आवंटन, सीनियरिटी, उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला और 18 राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों पर पड़ सकता है। केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि 11 मार्च के फैसले में स्पष्टीकरण दिया जाए, क्योंकि इस फैसले को लागू करने से बड़े स्तर पर असर पड़ सकता है। इसके तहत उन उम्मीदवारों को भी गैर क्रीमी लेयर माना जा सकता है, जिनके माता-पिता की आय अधिक है। केन्द्र सरकार ने मांग की है कि इसके लिए दो साल का समय दिया जाए, ताकि इस दौरान उन पदों की समानता तय करने की जरुरी प्रक्रिया पूरी की जा सके।

महाराष्ट्र के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कोई बेटी पैदा नहीं हुई थी। बच्ची के दादा लिम्बाजी दहिफाले गार्गी के बारे में बात करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा, "परिवार में बेटी का होना बहुत बड़ा सौभाग्य है। इतने वर्षों से हमें बेटी न होने का दुख था, वह इच्छा पूरी हो गई है।" लिम्बाजी ने कहा कि उन्होंने अपनी दोनों बहुओं को अपनी बेटियों की तरह माना है और अपनी पोती को संगीत और नृत्य के साथ रथ में घर लाकर वे बेहद खुश हैं।

नाहरगढ़ जैविक उद्यान में बाघ के हमले से महिला श्रमिक की मौत

सात महिला श्रमिक एन्क्लोज़र न. 16 के पास घास काट रही थीं, जब अचानक बाघ बाहर आ गया

- वन विभाग ने बाघ एन्क्लोज़र के प्रभारी को, प्रथम दृष्टया कर्तव्य में लापरवाही मानते हुए निलंबित कर दिया।
- उत्तेजित ग्रामीणों के साथ हुई सहमति के अनुसार, मृतका के परिवार को 10 लाख रूपए की मुआवजा राशि, दो आश्रितों को संविदा पद पर नौकरी तथा डेयरी बूथ आवंटित करना तय हुआ।

जयपुर, 2 सितम्बर। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में बुधवार सुबह बाघ के हमले से एक महिला श्रमिक की मौत हो गई। हादसा एन्क्लोज़र नंबर 16 के पास हुआ। घटना के समय सात महिला श्रमिक घास काटने और सफाई का काम कर रही थीं। जब वे बाघ के एन्क्लोज़र में दाखिल हुईं, तब बाघ अंदर बने पिंजरे में बंद था।

लेकिन अचानक किसी ने पिंजरे का गेट खोल दिया और अचानक ही बाघ पिंजरे से बाहर निकलकर महिलाओं के नजदीक पहुंच गया। महिलाओं ने पेड़ और सुरक्षा जाल पर चढ़कर जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन नांगल सुसावतान निवासी सुगना देवी बाघ की चपेट में आ गई। बाघ ने उसे झपटकर नीचे गिराया और हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाघ को तत्काल काबू कर वापस पिंजरे में बंद किया गया।

मृतका की बहन और मौके पर मौजूद अन्य महिलाओं ने आरोप लगाया कि वे करीब आठ वर्ष से यहां काम कर रही हैं। सामान्य तौर पर उन्हें सुबह 9 बजे काम के लिए बुलाया जाता था, लेकिन बुधवार को सुबह 8 बजे ही बुला लिया गया था। करीब 9 बजे अचानक बाघ दिखाई दिया। सुगना देवी घास पटककर जान बचाने के लिए अन्य महिलाओं की ओर दौड़ी। छह महिलाएं रेलिंग के जाल और तारों के ऊपर चढ़कर किसी तरह सुरक्षित निकल गईं। सुगना भी जाल पार करने का प्रयास कर रही थी, तभी पीछे से बाघ ने उसे झपट लिया।

महिलाओं का आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात वनकर्मी हंसा देवी ने बिना स्थिति देखे एन्क्लोज़र के अंदर बने बाघ के पिंजरे का गेट खोल दिया, जिसके कारण बाघ खुले एन्क्लोज़र तक पहुंच गया। हालांकि, घटना की वास्तविक वजह और सुरक्षा व्यवस्था में चूक की स्थिति, जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

नाहरगढ़ जैविक उद्यान में बाघ के हमले से महिला श्रमिक की मौत के मामले में वन विभाग ने बाघ एन्क्लोज़र के प्रभारी को प्रथम दृष्टया कर्तव्य में लापरवाही और सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन में चूक के चलते निलंबित कर दिया है। मामले की विस्तृत जांच के लिए सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) स्तर के अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर आशीष कुमार ने कहा कि एसीएफ के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित कर दी गई है। प्रारंभिक जांच के तहत गार्ड हंसा को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

हादसे की सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। आमेर थाना पुलिस भी पहुंची। बड़ी संख्या में ग्रामीण और मृतका के परिजन पार्क परिसर में जमा हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार करते हुए धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, आर्थिक मुआवजा और दोषी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आमेर विधायक प्रशांत शर्मा सहित, अन्य जनप्रतिनिधि भी धरने में पहुंचे।

काफी देर तक प्रशासन, वन विभाग और ग्रामीणों के बीच बातचीत चली।

सहमति के अनुसार, मृतका के परिवार को 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी। परिवार के दो आश्रितों को संविदा पर नौकरी देने तथा एक डेयरी बूथ आवंटित करने पर भी सहमति बनी है। वहीं, एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा। दोषी वन विभाग कर्मचारी के खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है।

नेपाल की बाढ़ से बिहार में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चेतावनी इस चिंता के बीच दी गई है कि सीवेज, मरे हुए जानवर और अन्य दूषित पदार्थ नदी तंत्र में पहुंच गए हैं।

लेकिन क्या इंसानी शवों के अवशेषों की मौजूदगी का मतलब यह है कि बिहार में किसी बीमारी का प्रकोप हो सकता है?

यहां समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाढ़ का पानी आमतौर पर सिर्फ पानी नहीं होता। इसमें सीवेज, मल, जानवरों का कचरा, सड़ने वाली चीजें, कूड़ा, खेती से जुड़े दूषित पदार्थ और बीमारी फैलाने वाले दूसरे रोगाणु हो सकते हैं। जब ऐसा पानी कुओं, हैंडपम्प, तालाबों, खाने-पीने की चीजों या घरों में पानी रखने की जगहों में पहुंच जाता है, तो स्वास्थ्य पर इसका असर बाढ़ के काफी समय बाद तक रह सकता है।

बड़े नदी तंत्र के आसपास फल-फूलने वाली भारतीय सभ्यता सदियों से इस खतरे से परिचित रही है, लेकिन नेपाल की बाढ़ की इस आपदा के बाद इसके प्रभाव चिंताजनक हो गए हैं।

नेपाल की बाढ़ की आपदा अब नीचे की ओर भारत को प्रभावित करने लगी है। एनडीटीवी लाइफलाइन से बात करने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार को सतर्क रहना चाहिए, लेकिन घबराने की कोई वजह नहीं है।

एनिरा कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड की सीईओ, रोपन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक और संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार डॉ. सबीन कपासी ने कहा, "आमतौर पर इंसानी शव अपने आप में बड़े पैमाने पर बीमारी नहीं फैलाते। बाढ़ में सबसे बड़ा खतरा पूरे पानी के दूषित होने का होता है।"

नई दिल्ली के फोर्टिस मैमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संक्रामक रोगों की वरिष्ठ सलाहकार डॉ. नेहा रस्तोगी का कहना है कि नेपाल से बिहार में बाढ़ का पानी आने से लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है।

इसी प्रकार विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी कहना है कि प्राकृतिक आपदाओं में मरने वाले लोगों के शव आमतौर पर महामारी नहीं फैलाते। हालांकि, ऐसी स्थिति में अपवाद हो सकता है, जब लोगों की मौत किसी बहुत संक्रामक बीमारी से हुई हो या ऐसे इलाके में हुई हो जहाँ ऐसी बीमारियां पहले से फैली हों। शव, पानी को मल के जरिए दूषित कर सकते हैं और अगर ऐसा पानी बाद में पी लिया जाए तो दस्त जैसी बीमारियां फैल सकती हैं।

यह अंतर महत्वपूर्ण है। शवों से संबंधित डर के कारण तत्काल खतरे से हमारा ध्यान हटना नहीं चाहिये। असली खतरा, दूषित पानी का लोगों के घरों, कुओं, हैंडपंपों, खाने-पीने की चीजों और संभवत: पीने के पानी के स्रोतों तक पहुँचना है।

मोदी के प्रति ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और एक्शन की आजादी का निर्धारण भारत सरकार और खास तौर पर गृह मंत्रालय करेगा?

सरकार की आलोचना करने पर लोगों को उनके ट्वीट, सोशल मीडिया पॉडकास्ट और लिखे गए लेखों के लिए उठाया जा रहा है।

पैलेट गन से घायल एक प्रदर्शनकारी की एफआईआर दर्ज करने में संसद मार्ग पुलिस थाने को सात घंटे लग गए, क्योंकि इसकी अनुमति गृह मंत्री से लेनी थी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के उत्तराखंड दौरे के बाद हुए शुद्धिकरण के खिलाफ प्रदर्शन करने पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर तुरंत दर्ज कर दी गई। जिस "नए भारत" का इतना प्रचार किया जा रहा है, वह मोदी और शाह द्वारा बनाया गया ऐसा भारत है, जहां स्वतंत्रता का प्रयोग केवल उन्हीं के बनाए नियमों के अनुसार किया जा सकता है।

यूपी में धन सम्पन्न लोगों को टिकट देने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कांग्रेस ने 399 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद केवल दो सीटें जीती थीं।

2024 के लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन और उत्तर भारत में राहुल गांधी की बढ़ती स्वीकार्यता (जैसा कि पार्टी नेताओं का कहना है) से उत्साहित कांग्रेस, समाजवादी पार्टी को अधिक बराबरी वाला सीट बंटवारा करने के लिए मजबूत संकेत दे रही है।

सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने हाल ही में सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि "कांग्रेस केवल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को आगामी चुनाव में सरकार बनाने में मदद करने के लिए सीटों पर समझौता करके खुद को बर्बाद नहीं करेगी।"

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेन्द्र पाल गौतम भी 403 विधानसभा सीटों में से 50 प्रतिशत सीटों की मांग पर जोर दे रहे हैं। इसी तरह, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के कम से कम दो प्रमुख नेताओं ने इंडिया टुडे को बताया कि पार्टी सीटों के "बराबर बंटवारे" पर जोर दे रही है और किसी भी स्थिति में 115-120 सीटों से कम पर समझौता नहीं करेगी।

इस बीच, अखिलेश यादव ने कहा है कि भविष्य के चुनावों में भी सहयोगी दलों के साथ गठबंधन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इसका फार्मूला "सीटें नहीं, जीत" होगा।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने सपा के साथ गठबंधन में 114 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे।

पार्टी अब इस तर्क को और मजबूती से आगे बढ़ा रही है कि दलित, अल्पसंख्यक और गैर-यादव ओबीसी मतदाता तेजी से राहुल गांधी के समर्थन में आ रहे हैं, खासकर संविधान और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर।

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, "हमारे पास आगे की कई योजनाएं पाइपलाइन में हैं। बलिया से मेरठ तक की यात्रा (जिसमें अवध शामिल होंगे) से लेकर सामाजिक न्याय और संविधान पर केन्द्रित अभियान तक, कांग्रेस का सबसे अच्छा प्रदर्शन अभी आना बाकी है।"

पार्टी को उम्मीद है कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव में किए गए अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ाएगी, जब उसने उत्तर प्रदेश में छह सीटें जीती थीं।

"संगठन सृजन" पहल के जरिए की जा रही संगठनात्मक तैयारियों और सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में चल रही तैयारियों को देखते हुए, कांग्रेस का मानना है कि गठबंधन में अधिक हिस्सेदारी के लिए उसका दावा मजबूत है।

पार्टी के अंदरूनी लोगों का यह भी कहना है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार लगातार दो कार्यकाल और करीब एक दशक तक सत्ता में रहने के बाद अब सत्ता विरोधी माहौल का सामना करने लगी है। इससे कांग्रेस के चुनावी आकलन को और बल मिल रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने मनन कुमार मिश्रा की शक्तियां सीमित कीं

नई दिल्ली, 02 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार, 2 सितंबर को बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा तब तक ही प्रो-टेम चेयरमैन हैं, जब तक कि नई बनी बीसीआई अपने पदाधिकारी नहीं चुन लेती।

- अदालत ने इन्हें बार काउन्सिल का लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ पदाधिकारी नहीं माना।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि बड़े नीतिगत फैसले भारत के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की सलाह से लिए जाएं, जो बीसीआई के स्थायी पदेन सदस्य होते हैं।

रघुराम राजन व पूर्व वित्त सचिव गर्ग की सोच नकारात्मक - पीयूष गोयल

नई दिल्ली, 02 सितंबर। केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के हालिया जीडीपी ग्रोथ आंकड़ों पर सवाल उठाने वाले आलोचकों को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने ऐसे आलोचकों को नकारात्मक सोच वाले लोग बताया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग और आरबीआई के गर्वनर रहे रघुराम राजन पर भी इशारों में निशाना साधा।

- गोयल ने कहा कि ये लोग पुरानी और नई जीडीपी सीरीज़ की भ्रामक तुलना कर रहे हैं

पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8 प्रतिशत रही है। इसका बचाव करते हुए गोयल ने कहा कि यह आंकड़ा हकीकत है। उन्होंने तर्क दिया कि आलोचक पुरानी और नई जीडीपी सीरीज के बीच भ्रामक तुलना कर रहे हैं।

गोयल ने कहा, नकारात्मक सोच वाले लोग जो चाहें कह सकते हैं, लेकिन 7.8 प्रतिशत की ग्रोथ एक हकीकत है।

गर्ग और राजन का नाम लिए बिना गोयल ने सरकार में उनके कामकाज पर सवाल उठाते हुए एक पूर्व वित्त सचिव और एक पूर्व रिजर्व बैंक गवर्नर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दोनों ही अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। 2012-14 के दौरान भारत को जिन आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, उन्होंने उनकी ओर इशारा किया। वाणिज्य मंत्री ने कहा, उन्हें यह भी नहीं पता कि समान चीजों की तुलना कैसे की जाती है। उन्होंने तर्क दिया कि आलोचक पुरानी सीरीज के तहत कैलकुलेट की गई ग्रोथ रेट की तुलना नई सीरीज के तहत कैलकुलेट की गई ग्रोथ रेट से कर रहे हैं, जबकि नई सीरीज में बेस ईयर ही बदल गया है।

सरकार आंकड़ों की बाजीगरी चाहती है- जयराम रमेश

नई दिल्ली, 02 सितंबर। कांग्रेस ने सरकार के 7.8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग के आकलन के अनुसार, वास्तविक जीडीपी वृद्धि करीब 2.6 प्रतिशत है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आंकड़ों की बाजीगरी के जरिए अर्थव्यवस्था की तस्वीर चमकाने की कोशिश कर रही है, जबकि यह जमीनी हकीकत से अलग है।

- उन्होंने कहा, मोदी सरकार जितना जीडीपी का ढोल पीटेगी, उतनी ही असलीयत सामने आयेगी।

कांग्रेस महासचिव (संचार) एवं राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कहा कि मोदी सरकार अपनी टीम और मीडिया के जरिए जितना फर्जी जीडीपी बढ़ोतरी का ढोल पीटेगी, उतना ही उसकी असलियत सामने आएगी। पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने इस दावे पर गंभीर सवाल उठाए हैं और उनका आकलन है कि वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.8 प्रतिशत के बजाय करीब 2.6 प्रतिशत है।

'अपने बयानों से भाजपा को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्होंने कहा, "हम सभी को जानबूझकर या अनजाने में सावधान रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने यह बात जानबूझकर कही थी और न मुझे लगता है कि उन्होंने इसे इरादतन कहा होगा।"

वेणुगोपाल ने राहुल गांधी के छात्रों के बीच पहुंच बनाने के अभियान का जोरदार बचाव किया। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद में हुए कार्यक्रम में कांग्रेस के पारंपरिक संगठनात्मक आधार से बाहर के युवा भी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे।

उन्होंने कहा, कल इलाहाबाद में वहां का दृश्य क्या था? वे लोग आम कांग्रेस कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस या एनएसयूआई के सदस्य नहीं थे। वहां भारत की वास्तविक जेन ज़ी मौजूद थी।

उन्होंने दावा किया कि कोटा और देहरादून में हुए कार्यक्रमों में भी इसी तरह की भागीदारी देखने को मिली थी।

वेणुगोपाल ने उत्तर प्रदेश सरकार पर इलाहाबाद के कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले कार्यक्रम के लिए जगह देने से इनकार करने का दबाव बनाया गया और बाद में यात्रा के रास्ते में अस्वच्छ स्थिति पैदा कर दी गई।

उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई का सामना करने वाले छात्रों के मुद्दे लगातार उठाए हैं। इनमें वे छात्र भी शामिल हैं, जो पैलैट गन से घायल हुए थे और वे महिला प्रदर्शनकारी भी शामिल हैं, जिनके साथ कथित तौर पर पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था।

वेणुगोपाल ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए प्रधानमंत्री आवास की ओर कांग्रेस के मार्च का भी उल्लेख किया और इसे जेन ज़ी के समर्थन में हाल के सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक बताया।

थरूर ने शुक्रवार को महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में कहा था कि राहुल गांधी का 'छात्रों की गूंज' अभियान कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शनों में उठाए गए कई मुद्दों को ही उठा रहा है। जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस का कार्यक्रम जंतर-मंतर के आंदोलन जितना प्रभावी क्यों नहीं रहा, तो थरूर ने जवाब दिया, "सही बात है। और इसी वजह से हमें खुद से पूछना चाहिए कि हमसे क्या चूक हुई।"

उन्होंने कहा, "क्या हम छात्रों की बात सुनने में नाकाम रहे? क्या हम लोगों की नब्ज पर हाथ रखने की पुरानी कहावत पर खरे नहीं उतरे? क्या जेन ज़ी की नब्ज पर हमारी पकड़ नहीं रही? यह ऐसी बात है, जिस पर हमें गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

बाद में थरूर ने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी को उनकी पार्टी या उसके नेतृत्व पर हमले के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनका कहना केवल इतना था कि राजनीतिक दलों को युवा पीढ़ी के लिए खुद को और अधिक खोलना चाहिए और युवाओं को, राजनीति को दिशा देने में भूमिका निभाने के अवसर देने चाहिए।

रिटायर्ड एयर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अन्य जिम्मेदारियों के अलावा सीईओ संस्था के अधिकारियों, पदाधिकारियों, कर्मचारियों और स्टाफ के लिए सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकारी के रूप में काम करेंगे। सीईओ ट्रस्ट की वर्तमान गतिविधियों के कुशल प्रबंधन और भविष्य के विकास को सुनिश्चित करने के साथ-साथ सभी वैधानिक, नियामकीय और ट्रस्ट डीड से जुड़ी आवश्यकताओं के अनुपालन की जिम्मेदारी भी संभालेंगे।

यूपी में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कवायद" करती है, जबकि वास्तव में वह उन लोगों के खिलाफ लड़ रही है, जो भगवा पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ओवैसी के करीबी माने जाने वाले वकार ने नई दिल्ली के अकबर रोड स्थित पार्टी कार्यालय में एआईसीसी के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेन्द्र पाल गौतम, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और एआईसीसी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की।

एक प्रेस वार्ता में वकार ने कहा, "जमीनी स्तर पर हम भाजपा से नहीं लड़ते; हम कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (सपा) से लड़ते हैं; हम हर उस व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो भाजपा को हटाना चाहता है।" उन्होंने कहा, "इसलिए मुझे लगा कि अगर हम विपक्ष से ही लड़ते रहेंगे और उसे बढ़ने नहीं देंगे, तो हम भाजपा की मदद कर रहे हैं। मैंने फैसला किया कि अगर हम सच्चे राष्ट्रवादी हैं और ईमानदारी से भाजपा को हटाना चाहते हैं, तो हमारा उद्देश्य भाजपा से लड़ना होना चाहिए। अगर हम भाजपा के दुश्मनों से लड़ रहे हैं, तो हम भाजपा के दोस्त हैं।" वकार ने कहा, "हकीकत में, अगर पूरे देश में कोई भाजपा से लड़ रहा है, तो वह कांग्रेस, राहुल गांधी और उनके लोग हैं।"

एसआईआर के जरिये भाजपा को चुनाव जिताने की कोशिश -कपिल सिब्बल

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मतदाताओं के नाम थोक में हटाने पर रोक लगाने की मांग की

नई दिल्ली, 02 सितंबर। राज्यसभा सांसद और पूर्व केन्द्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग की ओर से कई राज्यों में चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर के जरिए मतदाता सूची में हेरफेर की कोशिश हो रही है और इसका मकसद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को चुनाव जिताने में मदद करना है। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से इस प्रक्रिया के तहत मतदाताओं के नाम थोक में हटाए जाने पर रोक लगाने की मांग की है। सिब्बल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि यह 'बहिष्कार की राजनीति' है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के एजेंट मुस्लिम मतदाताओं को निशाना बनाकर उनके नाम हटाने के लिए बड़ी संख्या में फॉर्म जमा कर रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस तरह की 'बल्क डिलीशन' यानी बड़ी संख्या में नाम हटाने की प्रक्रिया रोकने की अपील की।

- कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर मतदाता सूची से ऐसे लोगों के नाम हटाने की कोशिश की जा रही है, जो वर्षों से उसी जगह रह रहे हैं, तो यह बहुत गंभीर मामला है।

कपिल सिब्बल ने अपने आरोपों के समर्थन में "द इंडियन एक्सप्रेस" की एक रिपोर्ट का हवाला दिया। रिपोर्ट के मुताबिक, झारखंड के गोड्डा जिले में भाजपा से जुड़े लोगों की ओर से कुछ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए आवेदन दिए जाने का दावा किया गया है। इनमें बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शामिल होने की बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) ने भी कुछ मामलों को लेकर आपत्ति जताई। बीएलओ आम तौर पर सरकारी कर्मचारी होते हैं, जिन्हें चुनाव संबंधी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर मतदाता सूची से ऐसे लोगों के नाम हटाने की कोशिश की जा रही है, जो वर्षों से उसी जगह रह रहे हैं, तो यह बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदाता सूची का सही होना बेहद जरूरी है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिब्बल ने फॉर्म-7 का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में फॉर्म-7 एक साथ जमा किए जा सकते हैं। उनके मुताबिक, कोई व्यक्ति 45, 100 या 400 तक फॉर्म लेकर यह मांग कर सकता है कि इतने मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए जाएं। कपिल सिब्बल ने दावा किया कि इस तरह के आवेदन में नाम हटाने की मांग की जा सकती है और बाद में अगर शिकायत गलत साबित होती है तो भी कोई खास असर नहीं पड़ता।

कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर अदालत यह मानकर चलती है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग की निगरानी में हो रही है और इसलिए इसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो सकती, तो यह चिंता का विषय होगा।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422, 226423, जालौर। फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908